पृथक अपने अपने अड्डे बनाने की तैयारी कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख): सोवियत सरकार ने इस बात का खंडन किया है कि वह हिन्द महासागर में किसी प्रकार का सैनिक अड्डा बनाने की योजना बना रही है । ब्रिटिश हिन्द महासागर क्षेत्र में संयुक्त संचार सुविधाओं की व्यवस्था के लिए ग्रेट ब्रिटेन के साथ संयुक्त राज्य अमरीका की एक संधि व्यवस्था हुई है । भारत सरकार की यह नीति रही है कि हिन्द महासागर किसी भी शासन सत्ता से स्वतन्त्र रहे और शान्ति तथा सहयोग का इलाका बना रहे । इसलिए हम इस क्षेत्र में विदेशी सैनिक अड्डों के विरुद्ध हैं और हमारे विचारों से सम्बद्ध देशों को अवगत करा दिया गया है ।

Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees in Bharat electronics Ltd., Bangalore

4265. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees employed in Bharat Electronics Ltd., Bangalore during the last two years;

(b) the number of vacancies filled, and the number of vacancies not filled;

(c) if the vacancies are not filled, the reasons therefor; and

(d) the period for which such vacancies are there?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M. R. KRISHNA): (a) The information is given below:—

Calendar year	No. of Scheduled castes/scheduled tribes candidates employed in Bharat Electronics Ltd.
1967	154
1968	233

(b) The position is as under :

Calendar year	No. of vacancies filled	No. of vacancies not filled
1967	1220	213
1968	1490	2053

(c) The "vacancies" not filled as indicated in the reply to part (b) represent and take into account the future personnel requirement for the expansion of production, having regard to the lead time for phase recruitment and training. These figures relate to total vacancies and not reserved vacancies. The total sanction is reviewed by the company from time to time, taking into account the actual factory load, efficiency, and changes in methods of production etc., and the vacancies are filled on a phased programme.

(d) In view of the reply to part (c), the time and labour involved in collecting the requiste information will not be commensurate with the results.

Trade Delegations

4266. SHRI MANGALATHUMADAM: Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that delegations are sent separately by the various Export Promotion Councils

abroad to explore export possibilities; and

(b) if so, whether it is proposed to have a centralised agency to do this job in the Ministry?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEVAK): (a) and (b). Export Promotion Councils look after a specified group of commodities. Trade delegations for exploration of export possibilities of the commodities under the jurisdiction of a specific Export Promotion Council are sponsored by that Council. Multi-commodity delegations however are sent under the aegies of the Federation of Indian Export Organisations, which is the apex body coordinating the export efforts of all Export Promotion bodies in the country.

देहू छावनी में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये बनाये गये मकान

4267. **श्री एस० एम० जोशी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहू छावनी में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिए लगभग 1200 मकान बनाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल अनुमानित लागत कितना है और उन पर कितना व्यय किया गया है ;

(ग) क्या सम्बन्धित अधिकारी ने कार्य पूरा होने पर समापन प्रमाण पत्र जारी कर दिया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार को पता है कि जिस प्रकार से मकान बनाए गए हैं वे उस माडल के स्तर के नहीं हैं जिसके अनुसार उन्हें बनाया जाना था ; और क्या सरकार का विचार समूचे निर्माण कार्य के बारे में जांच कराने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, मकानों की संख्या 1,232 है।

(ख) 1,62,68,400 रुपये की अनुमानित लागत पर एक परियोजना मंजूर की गई है। अब तक 151 लाख रुपये की धन राशि इस पर लग चुकी है।

(ग) वृक्षवर्धन और जल निकाय क्षेत्र की व्यवस्था को छोड़कर, जिन पर कि काम चल रहा है, अन्य कार्यों के लिए पूर्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं।

(घ) ठेकेदारों को जो धन राशि देनी थी वह दी जा चुकी है।

(ङ) मकानों का निर्माण स्वीकृत डिजाइनों और विशिष्ट विवरणों के अनुसार किया गया है, परिणामतः सारे निर्माण कार्य की जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

देहु छावनी में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये बनाये गये मकान

4268. **श्री एस० एम० जोशी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहू छावनी में बनाए गए 1200 मकानों में से कितने मकान प्रतिरक्षा कर्मचारियों को 30 जून, 1969 तक अलाट किए गए और कितने कर्मचारियों ने उन पर कब्जा कर लिया है ;

(ख) कितने कर्मचारियों को मकान अलाट करने से इन्कार कर दिया गया है ; और

(ग) अब तक कितने मकान अलाट नहीं किए गए हैं और उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). जानकारी प्राप्त की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।